मौजूदा दवाओं के जरिये कोरोना से जंग

मुकुल व्यास

दुनियाभर के वैज्ञानिक नये वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि कुछ यह जानना चाह रहे हैं कि क्या मौजूदा दवाओं से कोविड-19 पर काबू पाया जा सकता है। भारत में प्लाज्मा थेरैपी की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें कोरोना से स्वस्थ होने वाले व्यक्ति के रक्त का प्रयोग बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्ति के रक्त में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी तत्व उत्पन्न हो जाते हैं जो बीमार व्यक्ति को रोग से लड़ने में मदद कर सकते हैं। बहुत ही गंभीर मरीजों को ठीक करने के लिए इस थेरैपी का प्रयोग हुआ है। वुहान के डॉक्टरों ने कोरोना के दस मरीजों को ठीक करने के लिए इस थेरैपी का प्रयोग किया था। इन मरीजों की हालत बहुत ज्यादा ख़राब थी। चीन की सफलता से उत्साहित होकर अमेरिका, फ्रांस और इटली में इस थेरैपी के क्लीनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। केरल और दिल्ली ने इस थेरैपी पर परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय डॉक्टरों को क्लीनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने इसकी सुरक्षा का आकलन करने के लिए इस पर क्लीनिकल ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है।

कोविड-19 से निपटने के लिए मौजूदा दवाओं में रिसर्चरों ने बीसीजी वैक्सीन को खास तौर से चुना है जो फेफड़ों में बैक्टीरिया की वजह से होने वाली टीबी (तपेदिक) को रोकने के लिए दी जाती है। दुनिया में इस वैक्सीन पर ट्रायल शुरू हो चुके हैं। मकसद यह कि क्या यह सौ साल पुरानी दवा हमारे नए दुश्मन कोरोना से हमारा बचाव कर सकती है। प्रारंभिक विश्लेषणों से पता चला है कि जिन देशों ने इस वैक्सीन को अपनाया है, वहां कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर उन देशों से बहुत कम है, जिन्होंने इस वैक्सीन का प्रयोग नहीं किया है। भारत और जापान सहित देशों में शिशु के जन्म के बाद अनिवार्य रूप से बीसीजी का टीका लगाया जाता है जबकि फ्रांस, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड ने यह टीका लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। अमेरिका, इटली और हॉलैंड जैसे देशों ने कभी भी इस टीके को अनिवार्य नहीं किया। पुर्तगाल में बीसीजी का टीका अनिवार्य है। वहां कोविड के 18841 से अधिक मामले हैं जबकि वहां 629 मौतें हुई हैं। दूसरी तरफ उसके पड़ोसी स्पेन में 184948 से अधिक मामले हो चुके हैं और 19315 लोगों की जान चली गई।

बीसीजी वैक्सीन जिंदा माइकोबैक्टीरियम रोगाणु के शिथिल रूप से तैयार की जाती है। यह सबसे पहले पेरिस में 192० के दशक में विकसित हुई और विश्व के सभी हिस्सों में भेजी गई। अब अनेक देशों के पास बीसीजी के टीके हैं जो उन्होंने जीवित बैक्टीरिया की अलग-अलग फॉर्मूलेशन से बनाए हैं। इन टीकों की प्रतिरोधक क्षमता भी भिन्न है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अनुसार जीवित रोगाणुओं से तैयार की जाने वाली वैक्सीन बहुत तगड़ा इम्यून रेस्पांस देती है जो काफी लंबे समय तक रहता है। कभी-कभी उनका प्रभाव जीवनपर्यन्त रहता है। दूसरी तरफ, फ्लू जैसी वैक्सीनें इतनी तगड़ी इम्युनिटी नहीं प्रदान कर पातीं।

कोविड से निपटने के लिए मलेरिया की दो दवाएं, क्लोरोच्चिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोच्चिन काफी चर्चित हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इन दवाओं को गेम-चेंजर बताते हुए कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए इनके प्रयोग की जोरदार वकालत कर डाली। हालांकि, इन दवाओं के कारगर होने का कोई समुचित प्रमाण नहीं मिला। विभिन्न देशों में हैल्थ वर्कर्स को बचाव के लिए यह दवा दी जा रही है। भारत ने अमेरिका सहित अनेक देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोच्चिन की सप्लाई भेजी है। ब्राजील में इस दवा को लेकर चल रहा क्लीनिकल ट्रायल बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि अनेक मरीजों में दिल की धड़कन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। वैज्ञानिकों का ध्यान रेमडेसीविर नामक दवा पर भी गया है। यह दवा छह साल पहले इबोला वायरस से निपटने के लिए तैयार की गई थी। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के दौरान दर्शाया है कि यह दवा कोरोना वायरस के उस मैकेनिज्म को रोकने में कामयाब रही है, जिसकी वजह से यह वायरस कोविड बीमारी फैलाता है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ है। इससे पहले इन्हीं रिसर्चरों ने फरवरी में इसी पत्रिका में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में कहा था कि प्रयोगशाला में यही दवा मेर्स वायरस के खिलाफ भी असरदार साबित हुई थी जो वर्तमान कोरोना वायरस से मिलता-जुलता है॥

संपादकीय

लॉकडाउनः बंदिशों के बीच

देश में लॉकडाउन का एक महीना पूरा हो गया। जब इसकी घोषणा हुई थी तो यकीन करना मुश्किल था कि पूरा देश कभी बंद भी हो सकता है। लेकिन तमाम सीमाओं और कठिनाइयों के बावजूद लोगों ने इसकी बंदिशों का पालन किया। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो देश में ऐसे मामले अबतक 5 या 1 गुना ज्यादा होते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि भारत ने एकदम सही समय पर लॉकडाउन का रास्ता अपना लिया। लेकिन लॉकडाउन की घोषणा होते ही लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर-कामगार जिस तरह अपने-अपने गांवों की ओर पैदल ही चल पड़े, उससे अफरातफरी मच गई। लगा कि व्यवस्था के हाथ से सब कुछ निकल गया और भयानक अराजकता फैलने वाली है।

बहरहाल, हालात संभल गए। राज्यों ने अपना काम गंवा चुके मजदूरों के भरण-पोषण की व्यवस्था की। उनके खातों में पैसे डाले और कई अन्य तरीकों से उन्हें राहत पहुंचाई। इसी बीच दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तब्लीगी जमात का मामला सामने आया जिसने सनसनी फैला दी। पता चला कि एक धार्मिक आयोजन में दुनिया भर से आए 2 लोगों में से करीब 14 लॉकडाउन के पहले वहां से निकल नहीं पाए और कई दिनों तक वहीं फंसे रहे। बाद में इनकी बड़ी संख्या कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई और इनके संपर्क में आए लोग भी बीमारी के शिकार हुए। इस पर काफी हंगामा हुआ, राजनीति हुई और कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की। फिर कई जगहों से स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की खबरें आने लगीं लेकिन इस मामले में सरकार ने सख्ती से काम लिया। लॉकडाउन के पहले चरण से सबक लेते हुए सरकार ने इसके दूसरे चरण में संक्रमण की मात्रा के आधार पर देश को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा और बीमारी से ज्यादा प्रभावित इलाकों को सील कर दिया। इस सख्ती का अच्छा असर दिख रहा है लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या हो। क्या लॉकडाउन को आगे भी जारी रखना पड़ सकता है? अगर हां, तो मौजूदा पैमाने पर ही इसे जारी रखने के क्या नुकसान हैं?

सचाई यह है कि लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था तकरीबन बैठ गई है। प्रतिदिन 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। आर्थिक गतिविधियां जल्दी पटरी पर नहीं लौटीं तो बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या गंभीर हो सकती है। फिर लोगों के धैर्य की भी एक सीमा है। वे आखिर कब तक घरों में बंद रह सकते हैं? कुछ लोगों की शारीरिक और मानसिक बीमारियां बेकाबू हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ, सामाजिक सक्रियता शुरू होने के साथ ही संक्रमण बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। ऐसे में एक ही रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को जीवन पद्धति का हिस्सा बनाते हुए उत्पादन कार्य धीरे-धीरे शुरू किए जाएं। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर जांच की जाए क्योंकि बकौल डब्ल्यूएचओ, कोरोना अभी लंबे समय तक रहने वाला है।

सू- दोकू क्र.05

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.04 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

दिलों की डिस्टेंसिंग

ऐसे वक्त में जब देश कोरोना की महामारी के खिलाफ तमाम कष्टों के साथ लड़ रहा है, देश की गंगा-जमुनी तहजीब को पलीता लगाने की कोशिश हो रही है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को आंच आ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकता व भाईचारे का संदेश देना पड़ा। उनकी टिप्पणी तार्किक थी कि कोविड-19 महामारी जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा या भौगोलिक सीमा नहीं देखती। उन्होंने मुश्किल वक्त में एकजुट होने का आह्वान किया। दरअसल, निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के जलसे के बाद कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या सामने आने के बाद देश में वर्ग विशेष को लेकर तल्खी सामने आई। निस्संदेह यह जमात के आयोजन का वक्त नहीं था। साथ?ही जो लोग संक्रमित हुए अथवा जिनमें संक्रमण की संभावना थी, वे सामने नहीं आये। उनसे जुड़ी तमाम नकारात्मक खबरें सोशल मीडिया में तैरती रहीं,?जिसने एक काल्पनिक विचार उत्पन्न किया कि संक्रमण को इरादतन फैलाया जा रहा है। निस्संदेह इसमें निहित स्वार्थी तत्वों की भूमिका है, मगर जब जमात का सर्वेसर्वा यह कहता नजर आये कि कोई सामाजिक दूरी व बचाव की जरूरत नहीं है तो इससे नकारात्मक संदेश?गया। दरअसल, ऐसी सोच के मूल में अज्ञानता और धर्मांधता की भी भूमिका है जो निष्कर्ष देता है कि देश में वैज्ञानिक व प्रगतिशील सोच विकसित करने के लिए विश्वसनीय सूचना तंत्र जरूरी है। इस दौर में सोशल मीडिया की भड़काऊ भूमिका आग में घी डालने का काम कर रही है। इन माध्यमों का प्रयोग करने वालों का विवेक उनकी शिक्षा, परिपच्चता, सजगता और जवाबदेही पर निर्भर करता है। जाहिरा तौर पर इन मानकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है?जो आगामी वक्त में सामाजिक वातावरण विषाक्त कर सकते हैं। यह सचेत होने का वक्त है।

प्रधानमंत्री ने सरकारी एजेंसियों को स्पष्ट संदेश?दिया है कि उपचार, बचाव व राहत कार्यों में कहीं भी धार्मिक टैग से महामारी से प्रभावित लोगों की पहचान न की जाये। निस्संदेह देश-दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। महामारी से बचाव के लिए जो सख्त उपाय किये गये हैं, उनसे जीवन की जटिलताएं बढ़ी हैं। रोजी-रोटी का प्रश्न है। रोजगार पर मंडराते खतरे का प्रश्न है। वह भी ऐसे वक्त में कि कारगर इलाज के अभाव में महामारी कब तक असर दिखायेगी, कहना जल्दबाजी ही होगी। निस्संदेह देर-सवेर रोग पर विजय पा ही लायी जायेगी, मगर इस दौर में यदि सामाजिक कटुता जन्म लेती है तो उसका त्रास आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। जरूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया की निरंकुशता पर अंकुश लगे। विडंबना यह है कि इस माध्यम में संपादक नामक नियामक न होने के कारण यह बेलगाम हो गया है और तमाम घटक अपने मंसूबों के लिए इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। हालांकि, हाल ही में सामूहिक संदेश भेजने की गति पर नियंत्रण के प्रयास हुए हैं, कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हुई मगर हालात अभी भी नहीं बदले हैं। ऐसे में हम कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसे ही कुत्सित प्रयासों से कहीं दिलों की डिस्टेंसिंग का शिकार न बन जायें। देश के विभिन्न भागों से फेरीवालों व दुकानदारों से लेकर ग्राहकों तक से ?धार्मिक टैग के आधार पर व्यवहार की जो खबरें आ रही हैं, वह हमारे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर आंच लाती हैं। समाज के जिम्मेदार लोगों को ऐसी सोच के विरुद्ध मुहिम चलानी चाहिए। अन्यथा सामाजिक तानेबाने को क्षति पहुंच सकती है। हम अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। आने वाला समय खासा चुनौतियों से भरा होगा, खासकर जब लॉकडाउन के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश होगी। ऐसे में सेहत, रोजगार व भोजन की उपलब्धता हमारी प्राथमिकता हो। साथ?ही हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी आंच न आने पाये।

uohu 'kkgA